के लिए देश के कानून में लेखकों के लिए समुचित सुरक्षा उपायों का प्रावधान है ।

कुंवारी मातायें

3386. श्री अनंतराव देवसांकर दवे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हर वर्ष राज्य-वार कितनी अभागी कुंवारी मातायें बच्चों को जन्म देती हैं ;

(ख) कुंवारी माताओं और बच्चों को आर्थिक सहायता, सामाजिक दर्जा और उनके निभाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) अनाथालयों में रह रही कुंवारी माताओं और बच्चों को सामाजिक दर्जा दिलाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(घ) ऐसी लड़कियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो यौन उत्पीडन के बाद बच्चों को जन्म देती और क्या ऐसे बच्चों के विवाह के लिए सरकार के पास कोई योजना है और क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए किसी संस्था को स्थापना की है ;

(ङ) यदि हां, तो देश में ऐसी संस्थाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उनके क्या-क्या नाम हैं और क्या प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्रों आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता को ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी दी जाती है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं । इस संबंध में कोई सांख्यिकीय

(ख) और (ग) अविवाहित माताओं और उनके बच्चों के लिये कोई विशेष योजना नहीं है । परन्तु सरकार निर्धन परिवारों और महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु नोराड, स्वेप, आई.आर.डी.पी.डी.डब्ल्यू. सी. आर.ए., एस.ई.पी., सी.सी.ई. और वी.टी. तथा जागृति विकास कार्यक्रमों जैसे कई कल्याण और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है समाज में महिलाओं और बच्चों की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने तथा उनके प्रति समाज के रवैये में परिवर्तन लाने के लिये प्रचार माध्यमों से प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) यौन उत्पीड़न के बाद बच्चों को जन्म देने वाली लड़कियों की संख्या से संबंधी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार के पास ऐसे बच्चों और उनके विवाह आदि के लिए न तो कोई योजना है और न ही कोई संस्थान हैं। परन्तु सरकार ने 1993–94 के दौरान देश के अधिकतम आबादी वाले 11 शहरों में गलियों में घूमने वाले आवारा बच्चों के कल्याणार्थ एक योजना शुरू की है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

Project report submitted by Karnataka

3387. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Karnataka has submitted a revised project report to the Centre for training and employment programmes for rural women in handloom activities; and

(b) if so, the status of the project report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): (a) Yes, Sir. The

Government of Karnataka has submitted a revised Project.

(b) Karnataka Handloom Development Corporation Limited was sanctioned a Project for 'Training and Employment Programme for Rural Women in handloom activities with an approved outlay of Rs. 685.80 lakhs with the Government of India's commitment to the extent of Rs. 580.61 lakhs. Grants of Rs. 180 lakhs during the year 1990-91, Rs. 61.245 lakhs during the year 1991-92 and Rs. 184.74 lakhs during the year 1992-93 were released to bringing the total grant to Rs. 425.985 lakhs released to the Corporation up to 31st March 1993. Against the release of this amount an expenditure of Rs. 275.24 lakhs has been incurred by the Karnataka Handloom Development Corporation Limited upto June 1993 leaving an unspent balance of Rs. 150.745 lakhs. The sanction of the recasted cost estimates submitted is dependent upon the satisfactory progress both in physical and financial terms of the Project already sanctioned and the merits of the proposal.

Pathetic Condition of Government Schools in Delhi

3388. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appeared in Indian Express dated 18th June, 1993 stating that the condition of Government schools in Delhi is pathetic;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether any contingency plan is contemplated to improve the condition of the schools so as to improve the educational standards;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT OF EDUCATION AND DEPTT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (e) Yes, Sir. According to information furnished by Delhi Administration the result of Government schools including of those schools mentioned in the news item, has improved from 35.1 per cent to 40 per cent in Secondary and 55.1 percent to 61.5 percent in Senior Secondary. Dehi Administration has initiated various measures to ensure further improvement in the educational standards. Some of the measures are:

(i) perspective plan to improve infrastructure has been prepared upto year 2001.

(ii) inservice training of teachers has been started.

(iii) vacancies are being filled up on priority.

These measures are also in tune with most of the recommendations made by the Committee which was set up under the Chairmanship of Shri A. K. Sharma.

Delhi Administration has further intimated that a crash programme has been taken up to improve the physical facilities of the schools.

Percentage of Literacy in States

3389. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the percentage of literacy in different States among Males and Females; and

(b) what steps Government are taking to increase it?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) A statement showing the literacy rates